



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2015/अग्रहायण 16, 1937

No. 386]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2015/AGRAHAYANA 16, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 23 नवंबर, 2015

सं. टीएएमपी/33/2007-सीओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963, (1963 का 38 वाँ) की धारा 49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा कोचीन पत्तन न्यास के पत्तन भूखंडों हेतु प्रचलित पट्टेदारी किराया की वैधता को यहां इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण संख्या टीएएमपी/33/2007—सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास

आवेदक**आदेश**

(नवंबर 2015 के 5वे दिन पारित)

यह प्रकरण कोचीन पत्तन न्यास के पत्तन भूखंडों के लिए पट्टेदारी किराये की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1. सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के लिए पट्टेदारी किराए इस प्राधिकरण द्वारा, आदेश सं. टीएएमपी/33/2007-सीओपीटी दिनांक 4 मई 2010 के माध्यम से संशोधित किए गए थे। कथित आदेश भारत का राजपत्र में राजपत्र सं. 160 के जरिए 11 जून 2010 को अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के पट्टेदारी किराए 11 जुलाई 2015 अर्थात् 5 वर्ष के लिए वैध थे। इस

प्राधिकरण ने, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के पट्टेदारी किरायों की वैधता को दिनांक 17 अगस्त 2015 के आदेश द्वारा **30 सितंबर 2015** तक विस्तारित किया है।

2.2. जैसाकि, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के पट्टेदारी किरायों की वैधता 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो रही थी, सीओपीटी ने दिनांक 30 सितंबर 2015 के अपने ई-मेल के जरिये सूचित किया कि मूल्यनिर्धारक ने प्री-ड्राफ्ट मूल्यनिर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है। महापत्तनों के लिए भूमि नीति मार्गदर्शी 2014 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए रिपोर्ट को फाइनलाइज करने में कम से कम एक माह और लगेगा।

2.3. उपरोक्त स्थिति के मद्दे नजर सीओपीटी ने पट्टेदारी किरायों के संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 15 नवंबर 2015 तक समय-विस्तार के लिए अनुरोध किया है। तथापि, सीओपीटी ने, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों की मौजूदा पट्टेदारी किराया दरों की वैधता की विस्तार के लिए अनुरोध नहीं किया है।

3.1. सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के वर्तमान पट्टेदारी किरायों की वैधता 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो गई है, जब तक कि वैधता विस्तारित नहीं कर दी जाती प्रशुल्क व्यवस्था में एक खालीपन बना रहेगा जो अवांछनीय है। इसलिए, यह प्राधिकरण, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के वर्तमान पट्टेदारी किरायों की वैधता को, इनके हाल ही में, समाप्त होने की तिथि से 31 दिसंबर 2015 तक अथवा सीओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के संशोधित पट्टेदारी किरायों की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित की जाती है।

3.2. मई 2010 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टेदारी किरायों की अनुसूची में सामान्य नोट 1 एक विशिष्ट शर्त प्रदान करता है कि प्रदत्त पट्टेदारी किराए, सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शियों के अनुरूप 2% वार्षिक की अपने आप वार्षिक वृद्धि के अधीन है। ऐसी स्थिति में, 2% की दर से वार्षिक वृद्धि, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के पट्टेदारी किरायों पर विस्तारित वैधता अवधि के दौरान लागू की जाती रहेगी। वार्षिक वृद्धि संबंधी धारा, भूमि नीति मार्गदर्शी 2014 के साथ-साथ संशोधित भूमि नीति मार्गदर्शी 2014 के भी अनुरूप है।

3.3. तथापि, इस विषय में, यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ मौजूदा पट्टेदारी किरायों का विस्तार वर्तमान परिदृश्य में खालीपन से बचने के लिए केवल एक अनन्तिम व्यवस्था है। सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के लिए निर्धारित किए जाने वाले पट्टेदारी किराये, सीओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर होंगे।

4. परिणाम स्वरूप और ऊपर प्रदत्त कारणों से, यह प्राधिकरण, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के वर्तमान पट्टेदारी किरायों की वैधता को 30 सितंबर 2015 से आगे (और) 31 दिसंबर 2015 तक अथवा सीओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर, 2% वार्षिक वृद्धि के साथ संशोधित पट्टेदारी किरायों की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है। सीओपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह संशोधित भूमि नीति मार्गदर्शी 2014 के लागू होने वाले प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, जैसाकि सीओपीटी ने स्वीकार किया था, सीओपीटी के पत्तन भूखंडों के पट्टेदारी किरायों के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 15 नवंबर 2015 तक हर हाल में प्रस्तुत कर दे।

टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/143/15(274)]

Tariff Authority for Major Ports**NOTIFICATION**

Mumbai, the 23rd November, 2015

No. TAMP/33/2007-COPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing lease rentals for port lands of Cochin Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports**Case No. TAMP/33/2007-COPT****Cochin Port Trust**

...

Applicant**ORDER**(Passed on this 5th day of November, 2015)

This case relates to extension of the validity of lease rentals for port lands of the Cochin Port Trust (COPT).

2.1. The lease rentals for port lands of COPT was revised by the Authority vide Order No.TAMP/33/2007-COPT dated 4 May 2010. The said Order was notified in the Gazette of India on 11 June 2010 vide Gazette No.160. The lease rentals for the port lands of COPT revised by the Authority were valid for five years, i.e. upto 11 July 2015. This Authority has extended the validity of the lease rentals for port lands of COPT till 30 September 2015 vide Order dated 17 August 2015.

2.2. As the validity of the lease rentals for port lands of COPT was to expire on 30 September 2015, the COPT vide its email dated 30 September 2015 has stated that the valuer has submitted the pre-draft valuation report and the discussions on the same are in progress. It may take atleast one more month to finalize the report complying with the relevant provisions of the Land Policy Guidelines for Major Ports, 2014.

2.3. In view of the above position, the COPT has requested for extension of time upto 15 November 2015 for the submission of the proposal for revision of the Lease Rentals. However, the COPT has not requested for extension of the validity of the existing lease rentals rate for port lands of COPT.

3.1. The validity of the existing lease rentals for port lands of COPT expired on 30 September 2015. Unless the validity is extended there will be a vacuum in the tariff arrangement, which is not desirable. This Authority, therefore, extends the validity of the existing lease rentals for port lands of COPT from the date of its expiry till 31 December 2015 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals of port lands of COPT based on the tariff proposal to be filed by the COPT, whichever is earlier.

3.2. The General Note 1 in the Schedule of lease rent approved by this Authority in May 2010 prescribes a specific condition that the lease rent prescribed is subject to automatic annual escalation @ 2% in line with the guidelines issued by the Government. That being so, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the lease rentals for port lands of COPT. The annual escalation clause is also in line with the Land Policy Guidelines, 2014 as well as in its revised Land Policy Guidelines, 2014.

3.3. However, in this regard, it is relevant here to mention that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the port lands of COPT will be based on a proposal to be filed by the COPT.

4. In the result, and for the reasons given above, this Authority extends the validity of the existing lease rentals for port lands of COPT, beyond 30 September 2015 upto 31 December 2015 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the COPT, whichever is earlier, with an annual escalation of 2%. The COPT is directed to file its proposal for revision of lease rents for port lands of COPT positively by 15 November 2015 as agreed by the COPT following the applicable revised Land Policy Guidelines, 2014.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/15(274)]